पेराई सत्र शुरू कराने में जुटी सरकार

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

आगामी पेराई सत्र में चीनी मिलें समय से चलवाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। खुद मुख्यमंत्री अलिखेश यादव इस मुद्दे को लेकर काफी गम्भीर हैं। वह हर हाल में समय से चीनी मिलें चलवाने पर जोर दे रहे हैं।

उन्होंने बीते चौबीस घण्टों में कई आला अफसरों से इस मुद्दे पर अलग-अलग राय मशविरा भी किया है। उधर 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा.डी.वाई.चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच निजी चीनी मिलों के संगठन यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करेगी। अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि अगर चीनी मिलें समय से नहीं चलीं तो पिछले साल की ही तरह प्रदेश की ही तरह इस बार भी किसानों का आन्दोलन भड़क सकता है। साथ ही विपक्षी सियासी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाते हुए प्रदेश सरकार को घेर सकती हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी की बैठक भी बुधवार को हुई। इसमें रंगराजन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप बाजार में प्रचलित चीनी के दाम से जोड़ते हुए किसानों को दिया जाने वाला गन्ने का भाव तय करने के लिंकेज फार्मूले पर बातचीत हुई। बैठक में लिंकेज फार्मूले को स्वीकार न किए जाने को ही समर्थन मिला। बैठक में प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय और गन्ना आयुक्त आदि आला अफसर मौजूद थे।

HINDUSTAN — 16/10/2014

Pg-No- 13